

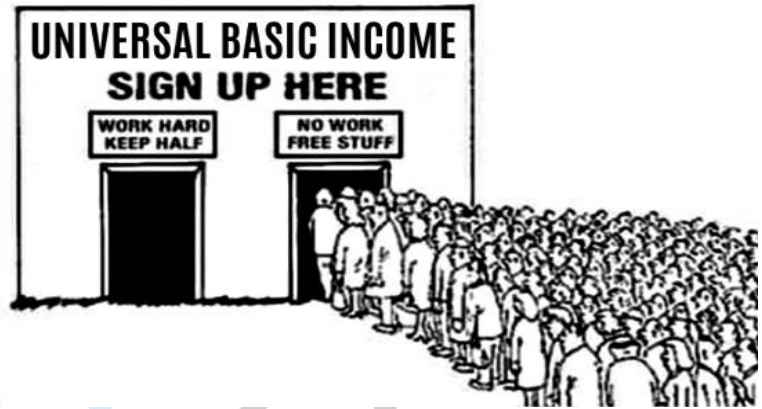
यूनिवर्सल बेसिक इनकम: भारत के कल्याणकारी राज्य का अगला स्तंभ

यूपीएससी प्रासंगिकता-

- जीएस पेपर टैग (जीएस पेपर 2 - शासन, कल्याणकारी योजनाएं)

चर्चा में क्यों?

भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) को लागू करने के विचार ने एक बार फिर ध्यान आकर्षित किया है। बढ़ती असमानता, ऑटोमेशन (स्वचालन) के कारण नौकरियों का बढ़ता नुकसान, और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में अक्षमता के कारण यह मांग उठी है कि भारत की कल्याणकारी वास्तुकला को UBI को केंद्र में रखकर फिर से डिज़ाइन किया जाए।



पृष्ठभूमि

भारत में केंद्र और राज्यों द्वारा चलाई जा रही 400 से अधिक कल्याणकारी योजनाएं हैं—खाद्य सब्सीडी से लेकर पेंशन और रोज़गार कार्यक्रमों तक। हालाँकि, इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी कम करना है, लेकिन वे अक्सर एक-दूसरे से ओवरलैप करती हैं, रिसाव (leakages) से ग्रस्त होती हैं, और योग्य लाभार्थियों को छोड़ देती हैं।

वहीं, भारत की अर्थव्यवस्था रोज़गार-रहित विकास (Jobless Growth) देख रही है—भले ही सकल घरेलू उत्पाद (GDP) बढ़ रहा है, सुरक्षित नौकरियों में वृद्धि नहीं हो रही है। बढ़ती असमानता और सामाजिक तनाव के साथ, विशेषज्ञ अब यह तर्क दे रहे हैं कि UBI जैसा एक एकल, प्रत्यक्ष आय समर्थन सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम स्तर की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) क्या है?

UBI एक निश्चित, बिना शर्त राशि है जो सरकार नियमित रूप से प्रत्येक नागरिक को देती है, चाहे उनकी आय, संपत्ति या रोज़गार की स्थिति कुछ भी हो।

मुख्य विशेषताएँ:

- सार्वभौमिक (Universal):** बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को कवर करता है।
- बिना शर्त (Unconditional):** इसके लिए कोई काम या पात्रता मानदंड आवश्यक नहीं है।

- **प्रत्यक्ष हस्तांतरण (Direct Transfer):** DBT (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के तहत आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है।
- **अधिकार-आधारित (Rights-based):** आय सुरक्षा को बुनियादी अधिकार के रूप में मान्यता देता है, न कि दान के रूप में।
- **सरलीकृत प्रणाली (Simplified System):** कई ओवरलैप हो रही कल्याणकारी योजनाओं को कम करता है।

IAS-PCS Institute

भारत में UBI की आवश्यकता

बढ़ती असमानता:

- शीर्ष 10% भारतीयों के पास राष्ट्रीय संपत्ति का लगभग 77% हिस्सा है (WID रिपोर्ट 2023)।
- आर्थिक विकास समान समृद्धि में परिवर्तित नहीं हुआ है।

रोज़गार-रहित विकास और ऑटोमेशन:

- 8.4% GDP वृद्धि (2023-24) के बावजूद, बेरोज़गारी उच्च बनी हुई है।
- ऑटोमेशन मौजूदा नौकरियों के 69% तक की जगह ले सकता है (मैकिन्से रिपोर्ट)।

जटिल कल्याणकारी प्रणाली:

- 400 से अधिक कल्याणकारी योजनाएँ दोहराव और रिसाव की ओर ले जाती हैं (नीति आयोग, 2022)।
- UBI ओवरलैप हो रहे कार्यक्रमों को बदलकर प्रशासनिक दक्षता ला सकता है।



सामाजिक कल्याण (Social Well-being):

- विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में भारत 137 देशों में से 126वें स्थान पर है।
- आर्थिक विकास ने जीवन संतुष्टि या सामाजिक सुरक्षा में सुधार नहीं किया है।

देखभाल कार्य की पहचान (Recognition of Care Work):

- महिलाओं का अवैतनिक कार्य भारत की GDP में लगभग 13% का योगदान देता है (ILO)।
- UBI ऐसे अदृश्य योगदानों को पहचान और समर्थन दे सकता है।

UBI का समर्थन करने वाले वैश्विक अनुभव

- **भारत (मध्य प्रदेश पायलट, 2011-13):** पोषण में सुधार ($\uparrow 25\%$), स्कूल उपस्थिति ($\uparrow 12\%$), और छोटे व्यवसायों ($\uparrow 17\%$) में सुधार हुआ।
- **फ़िनलैंड (2017-19):** प्रतिभागियों के बीच बेहतर मानसिक कल्याण और स्थिर रोज़गार।
- **केन्या (GiveDirectly):** खाद्य सुरक्षा और स्थानीय व्यवसाय के विकास में 40% सुधार।
- **ईरान (2011):** नकद हस्तांतरण ने सब्सिडी की जगह ली और बिना बड़ी मुद्रास्फ़ीति के गरीबी कम की।

UBI को लागू करने में चुनौतियाँ

राजकोषीय बोझ (Fiscal Burden):

- प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ₹7,620 का UBI भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 5% होगा, जो सार्वजनिक वित्त पर दबाव डालेगा।



लक्ष्यीकरण दुविधा (Targeting Dilemma):

- सार्वभौमिक समावेशन से बर्बादी हो सकती है यदि अमीर और गरीब को समान लाभ मिले।
- एक चरणबद्ध रोलआउट या "अर्ध-सार्वभौमिक" (Quasi-universal) मॉडल अधिक व्यवहार्य हो सकता है।

मुद्रास्फ़ीति का जोखिम (Inflation Risk):

- यदि आपूर्ति नहीं बढ़ती है, तो उच्च खर्च योग्य आय (disposable income) माँग को बढ़ा सकती है और मुद्रास्फ़ीति (Inflation) का कारण बन सकती है।

डिजिटल विभाजन (Digital Divide):

- खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, बैंक खातों की कमी और डिजिटल निरक्षरता ग्रामीण और आदिवासी आबादी को बाहर कर सकती है।

राजनीतिक प्रतिरोध (Political Resistance):

- मौजूदा सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त करने या विलय करने पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
- सुधार के लिए मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

आगे की राह (Way Forward)

- **धीरे-धीरे शुरुआत करें:** राष्ट्रव्यापी विस्तार से पहले महिलाओं, बुजुर्गों और अनौपचारिक श्रमिकों जैसे कमजोर समूहों के साथ शुरुआत करें।
- **प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि समाकलन:** संक्रमण के दौरान PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) और मनरेगा (MGNREGA) जैसी आवश्यक योजनाओं को UBI के साथ जारी रखें।
- **प्रगतिशील वित्तपोषण (Progressive Financing):** अमीरों पर धन, विरासत, और कार्बन कर लगाएं। UBI के लिए राजकोषीय जगह बनाने के लिए अकुशल सब्सिडी को कम करें।
- **IAM (जन धन-आधार-मोबाइल) अवसंरचना को मजबूत करें:** वास्तविक समय हस्तांतरण, शिकायत निवारण और समावेशन के लिए IAM प्रणाली में सुधार करें।
- **स्वतंत्र निरीक्षण:** रोलआउट, राजकोषीय स्वास्थ्य और पारदर्शिता की निगरानी के लिए एक सामाजिक सुरक्षा आयोग स्थापित करें।

निष्कर्ष

यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य की नींव बन सकता है—एक ऐसा राज्य जो सभी के लिए गरिमा, समानता और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ऑटोमेशन, नौकरी की अनिश्चितता और असमानता के समय में, UBI यह गारंटी देने का एक नया तरीका प्रदान करता है कि हर नागरिक के पास एक सुरक्षा जाल है।



आज भारत के लिए वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि “क्या हम UBI वहन कर सकते हैं?”—बल्कि यह है कि “क्या हम इसके बिना असुरक्षा और असमानता की बढ़ती लागत वहन कर सकते हैं?”

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न: “सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) में भारत की जटिल कल्याणकारी संरचना को सरल बनाने और सभी के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता है।” भारत के सामाजिक सुरक्षा ढाँचे के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

